



प्रसंगवश

अमित शाह का मिशन पंजाब कितना कामयाब होगा?

अरविंद मोहन

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड देना वजह हो या कुछ और, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पंजाब चुनाव को लेकर सक्रिय हैं, वह इस अपेक्षाकृत छोटे राज्य के चुनाव को भी काफ़ी दिलचस्प बना देता है। माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी बनाम अमित शाह की खींचतान ने भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नैया डुबोने का काम किया। इस बार भी पिछले प्रदर्शन को आधार बनाकर दोनों एक दूसरे का कद घटाना और अपना कद बढ़ाना चाहते थे। खैर। पंजाब में अमित शाह ने पिछली बार भी कम मेहनत नहीं की थी और इग्न से कारोबार को रोकने के नाम पर नेशनल हाइवे से जाने कितने मीटर दूर तक नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने और निगरानी का जिम्मा केन्द्रीय बलों को देने जैसे विवादास्पद क़ानूनी बदलाव भी किये। पर जब पार्टी खास प्रदर्शन नहीं कर पाई तो सारा दोष एनडीए के पार्टनर अकाली दल और इसके एक मंत्री और बादल परिवार के रिश्तेदार विक्रम मजीठिया के सिर मढ़ा गया। पिछली बार 117 सीटों में से बीजेपी को दो और अकाली दल को तीन सीटें मिली थीं। असल में बीजेपी अभी हाल तक प्रदेश की राजनीति में मुख्य खिलाड़ी रही भी नहीं थी और उसके लिए मैदान में ताल ठेंकाना और बड़ी-बड़ी बातें करना भी हक्का लगता था। लेकिन पिछली बार आम आदमी पार्टी (आप) ने जिस तरह से पंजाब को जीता वह बीजेपी के लिए ही नहीं किसी भी नए खिलाड़ी के लिए एक उदाहरण बन सकता है। आप 2014 में एक बार लोकप्रिय होकर पिट चुकी थी और 2017 में उसके

हाथ आती बाजी कांग्रेस ने जीत ली थी। पिछली बार आप ने कांग्रेस को पटखनी देकर अपना बदला ले लिया लेकिन पंजाब की राजनीति में दिग्गज रहे कांग्रेस और अकाली दल की गिरावट का बीजेपी कोई लाभ नहीं ले पाई तो सारा नजला अकालियों पर गिरा। उस पर भी यह हुआ कि अकालियों ने विवादास्पद कृषि कानून लाने पर बीजेपी और एनडीए से नाता तोड़ लिया था और अब भी वह मतदाता सूची की गहन पुनरीक्षा को लेकर संशय में है। पर चुनावी साथी की जरूरत बीजेपी को है तो अकालियों को भी बैसाखी चाहिए। अब सवाल यह बन गया है कि सीनियर पार्टनर कौन होता है अर्थात किसको ज्यादा सीटों पर लड़ने का अवसर मिलता है। बीजेपी को यहां तक ला देना भी अमित शाह और उसके साथी रणनीतिकारों की एक उपलब्धि है। और इसको असली ताकत लोकसभा के पिछले चुनाव के नतीजों से मिली है जो बीजेपी के लिए किसी के अनुमान से बेहतर रहे हैं। बीजेपी को विधानसभा की 23 सीटों पर बढ़त मिली तो शिरोमणि अकाली दल को मात्र नौ स्थानों पर। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 37 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली तो आप को 33 सीटों पर। जाहिर है इस रिजल्ट के आधार पर पंजाब की लड़ाई अभी खुली लगती है। और इसी आधार पर इस बार बीजेपी अकालियों से ज्यादा सीटों की बात चला रही है। पर कुछ बातें अमित शाह और बीजेपी के रणनीतिकारों को ध्यान में रखनी चाहिए। यह चुनाव लोकसभा का नहीं, विधानसभा का है और इसमें बीजेपी के पास मोदी जी जैसा कोई चेहरा नहीं है। अनेक कारणों से बीजेपी का संगठन अभी गाँव गाँव तक नहीं है और सिखों का वोट पाना उसके लिए खासा

मुश्किल है। अकालियों के संग लड़ने पर भी यही देखने में आया है कि मोर्चा के अकाली उम्मीदवार को तो हिन्दू वोट मिल जाते हैं लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को सिख वोट नहीं मिलते। दूसरी चीज बीजेपी द्वारा निरंतर अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके बाहरी लोगों- जिनमें फ़िल्म वालों, पूर्व नौकरशाहों और दूसरे दलों से आए नेताओं का अनुपात बहुत ज्यादा है, को चुनाव में अवसर देना भी है। ऐसे लोग केंद्र में मंत्री तक बने हैं जबकि स्थानीय कार्यकर्ता सिर्फ़ दरी बिछाने तक रह गए। जानी मानी हस्तियों को आखिरी वक्त टिकट देने की बात अभी छोड़ दें तो बीजेपी और इसके सूत्रधार अमित शाह ने काफी सारे नेता दूसरे दलों से तोड़े हैं। सबसे ताजा और बड़ा खेप तो राघव चड्ढा के नेतृत्व में आप के सांसदों को तोड़ने का है। अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे पुराने कांग्रेसी दिग्गज इधर आकर न कुछ कर पाए और न कुछ पा सके लेकिन अभी भी मनीष तिवारी से लेकर कई कांग्रेसी दिग्गजों के पाला बदलने की चर्चा उड़ती रहती है। कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी है और केन्द्रीय नेतृत्व जिस तरह बेपरवाह रहता है उसमें तय मानिए कि अभी कई विकेट गिरेंगे। और अगर कांग्रेस संभलकर लड़ी तो उसके लिए अपना खोया प्रदेश हासिल करके का अवसर है। उसके पास नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की फौज है और समाज के हर वर्ग में पैठ भी है। बात सिर्फ़ भरोसा बनाने की है और यह कम बड़ी शत नहीं है। और दूसरे दलों से लोग तोड़ने में बीजेपी ने अकाली दल को भी निशाना बनाया जिसके एक बड़े नेता मनजीत सिंह बादल को उसने अपनी ओर

कर लिया है। अभी तो अमित शाह और बीजेपी की केंद्र सरकार के निशाने पर आप है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के पहले की दिल्ली की स्थिति को याद कर सकें तो आपको वही दृश्य पंजाब में दोहराया जाता दिखेगा। अब आप के लोग कोई दूध के धुले हों और भगवंत मान की सरकार ने कोई झंड गाड़ दिए हों, यह नहीं है, लेकिन खुद मान साहब और उनके साथियों के साथ पिछले कुछ समय से केंद्र की एजेंसियों के माध्यम से जो व्यवहार हो रहा है, वह अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिंसोदिया, सत्येन्द्र जैन जैसों के साथ चले मामलों जैसा ही दिखता है। यहां कोई नई शराब नीति भी नहीं बनी है और न ठेका देने में संदेहास्पद तरीकों का आरोप है। पर जिस तरह भगवंत मान को विदेश से आने पर दिल्ली हवाई अड्डे पर ज्यादा खरीद और अशोषित सामान रखने के नाम पर पकड़ा गया वह विशुद्ध अपमान था और किसी अन्य मुख्यमंत्री के साथ ऐसे व्यवहार की याद आपको नहीं होगी। हमने देखा है कि जब राघव चड्ढा की अगुवाई में आप के सांसदों को तोड़ने का प्रयास हो रहा था तो वहां भी साम दाम दंड भेद सब उपाय करने की बात सामने आई। एक सांसद महाराज तो जेल भी गए और बाद में सब कुछ बीजेपी के वाशिंग मशीन में धुल गया। अब एंटी इंकम्बेन्सी से जुड़ा रही आप को कमजोर कड़ी मानकर उसकी घेराबंदी तेज करना और सही मुड़ा पर हमले बढ़ाना तो ठीक रणनीति है लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या इन सबसे बीजेपी पंजाब जीत पाएगी। (सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

तूफान ‘अर्नब’ से आंध्र-ओडिशा में हाहाकार

● 3 लोगों की मौत, 57 हजार लोग किए गए शिफ्ट ● 50 ट्रेनें-21 फ्लाइट रद्द, एमपी-यूपी में भी अलर्ट



विशाखापट्टनम (एजेंसी)। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ मंगलवार देर रात 3.30 बजे आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। यहां 125 से 135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश में 3 मौतें हुई हैं। राज्य के 31 घरों को नुकसान पहुंचा। 57 हजार

लोगों को शिफ्ट किया गया है। तूफान के कारण 50 ट्रेनें और विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर 21 फ्लाइट्स रद्द की गईं। ओडिशा में भारी बारिश के चलते 16 जिलों में स्कूल बंद हैं। यहां 30 हजार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 4,000 साइकलोन शेल्टर बनाए

गए हैं। विशाखापट्टनम में रात 27 अक्टूबर की सुबह 8.30 बजे से 28 अक्टूबर की सुबह 3 बजे तक, यानी करीब 18 घंटे में 200 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। यह जुलाई में होने वाली औसत बारिश के डेढ़ गुना से ज्यादा है। यहां जुलाई में औसतन 133 मिमी बारिश होती है।

मछलीपट्टनम से बालासोर तक समुद्र का रौद्र रूप

आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में तेज हवाओं और भारी बारिश से मौसम खराब है। वहीं, ओडिशा के बालासोर स्थित उदयपुर बीच पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। पूर्वी तट पर अलग-अलग जगहों के इन हालातों से हम समझ सकते हैं कि चक्रवात का असर केवल एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है। इसी बीच लोग इन लहरों में भी जिंदगी का लुक ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में चक्रवात अर्नब के असर से तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश हो रही है।

स्पेन में दो हाई-स्पीड ट्रेनें टकराईं, 39 की हुई मौत

● एक ट्रेन ने दूसरी को पीछे से जबरदस्त टक्कर मारी

मैड्रिड (एजेंसी)। स्पेन में बुधवार को दो हाई-स्पीड ट्रेनें टकरा गईं। स्पैनिश मीडिया के मुताबिक, हादसे में 39 लोगों की मौत की खबर है। स्पैनिश अखबार एल पाइस के मुताबिक, एक ट्रेन ने दूसरी को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर इमरजेंसी मेडिकल टीमें पहुंची हैं। यह घटना स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे हुआ। हादसे के बाद राजधानी मैड्रिड को दक्षिणी अंडालूसिया क्षेत्र से जोड़ने वाली रेल लाइन बंद कर दी गई। एक ट्रेन सुबह 8 बजे मैड्रिड से सेविल के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान दूसरी ट्रेन उससे टकरा गई। रेल नेटवर्क चलाने वाली कंपनी एंडेफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ट्रेन हादसे की खबर सुनकर वे सदमे में हैं। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और हादसे में प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं।

हरदीप सिंह पुरी एमपी से जाएंगे राज्यसभा

एल.गुरुगन के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। यह सीट केंद्रीय राज्य मंत्री एल गुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने इस सीट के लिए नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल, एल गुरुगन का कार्यकाल 2030 तक बचा हुआ था। उनके इस्तीफे के बाद एमपी से राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई थी। राज्यसभा सीट खाली होने के बाद अटकलें थीं कि इस बार पार्टी राज्य के ही किसी नेता को मौका देगी। लेकिन फिर से बाहरी को मौका दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया है। हरदीप सिंह पुरी अभी मांदि सरकार में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों और पेट्रोलियम मंत्री हैं। वह भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं।



जल्द आएंगे नामांकन करने भोपाल

गौरतलब है कि एमपी से राज्यसभा के लिए कई नामों की चर्चा चल रही थी। इस रেস में कुछ प्रदेश के भी नेता थे। सोमवार को कोर गुरु की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि राज्यसभा के लिए कुछ प्रदेश और कुछ बाहरी नेताओं के नाम का पैनाल भेजा गया है। बुधवार को दिल्ली से हरदीप सिंह पुरी के नाम पर मुहर लग गई है। अब जल्द ही उनके नामांकन की तारीख तय हो जाएगी।

लोन की किस्त नहीं चुकाई, एजेंट्स ने किसान को उठाया

● 3 दिन बाद फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में लाश मिली, 5 लोग गिरफ्तार

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के नांदेड जिले में 40 साल के किसान चंद्रकांत शिंदे का शव मिला है। शव निजी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में मिला। परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि लोन की किस्त नहीं चुकाने पर रिकवरी एजेंट्स ने चंद्रकांत को किडनीप किया था। तीन दिन बाद उनका शव मिला। चंद्रकांत शिंदे नांदेड जिले के मुदखेड तहसील के मलकोठा गांव के रहने वाले थे। पत्नी की शिकायत के अनुसार 22 अक्टूबर की शाम को दो अज्ञात लोगों ने उन्हें जबरन एक मोटरसाइकिल पर बैठाया और



किसान आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर

किसान आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले नंबर पर है। डेटा के मुताबिक 2023 में पूरे भारत में खेती-किसानी से जुड़े कुल 10,786 आत्महत्या के मामले सामने आए थे। इसमें से अकेले महाराष्ट्र में 4,151 केस थे। इनमें 4690 किसान थे और 6096 खेत मजदूर थे। आंकड़ों के कारण के आधार पर डेटा नहीं देता।

फाइनेंस कंपनी ऑफिस ले गए। पुलिस ने अभी यह नहीं बताया है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का। नांदेड एसपी के मुताबिक पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें फाइनेंस ऑपरेशन चलाने वाला मुख्य आरोपी असलम भी शामिल है। मामले की जांच के लिए 9 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई।

यूपी में जल्द बनेगा 90 किमी लंबा नया लिंक एक्सप्रेसवे

● भूमि अधिग्रहण शुरू, गंगा और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा

फतेहगढ़ (एजेंसी)। गंगा एक्सप्रेस-वे व आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जिले में बनने वाले लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण जल्द शुरू होगा। प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में निर्माण एजेंसी चयन के बाद तीन वर्ष में कार्य पूरा करने का निर्णय लिया गया है। निर्माण एजेंसी पांच वर्ष तक एक्सप्रेस-वे का अनुरक्षण करेगी। जिले में करीब 90 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा। इसे हरदोई जनपद के सवायजपुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे व दूसरी ओर इटावा में कुदरेल के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इससे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए कनेक्टिविटी रुथ भी मिलेगी। जिले में बनने वाले लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए प्रभासन ने जमीन अधिग्रहित करने को विशेष कैप लागवकर करीब 90 प्रतिशत अनुमति का बैनमा करा लिया है।



संक्षिप्त समाचार

इजराइल में उलटफेर, रुझानों में नेतन्याहू गठबंधन आगे

ओपिनियन पोल में हार का अनुमान था,ट्रम्प बोले-मेरे समर्थन से माहौल बदला

तेल अवीव (एजेंसी)। इजराइल में संसदीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। अब तक 76.8व वोटों की गिनती में नेतन्याहू गठबंधन 54 सीटों के साथ आगे है। वहीं, गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 47 सीटें मिलती दिख रही हैं। अरब पार्टियों के जॉइंट लिस्ट और राअम पार्टी को मिलाकर 19 सीटें मिलने का अनुमान है। इजराइली संसद में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 61 सीटें जरूरी हैं। चुनाव से पहले ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हार का अनुमान जताया गया था। चुनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने नेतन्याहू को मिली बढ़त का श्रेय लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि उनके समर्थन के बाद चुनाव का माहौल बदल गया। ट्रम्प के मुताबिक, पहले नेतन्याहू की हार का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब मुकाबला बराबरी का हो गया है और वे जीत भी सकते हैं। जॉइंट लिस्ट गठबंधन के अध्यक्ष युसुफ जबरीन ने कहा है कि उनका गठबंधन सत्ता में बदलाव लाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सरकार को हटाने की कोशिश करने वाली किसी भी पार्टी को उनसे बात करनी होगी। जबरीन ने कहा कि इजराइल के सामने दो रास्ते हैं- यहूदी वर्चस्व को जारी रखना या यहूदियों और अरब नागरिकों के बीच सहयोग कायम करना। अरब नेतृत्व वाली दो पार्टियों- जॉइंट लिस्ट और राअम को मिलाकर 19 सीटें मिलने का अनुमान है। इन्हें जॉइंट लिस्ट को 13 और राअम को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं।

लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरे भाजपा नेता

● **पटना में खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संभाला मोर्चा**

पटना (एजेंसी)। पटना में भाजपा की ओर से बुधवार को ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत पदयात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। पदयात्रा शुरू होने से पहले वह मंच से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम





आतंकी साजिश थी यहूदी प्रार्थनास्थल के पास आगजनी

● केरलम का मामला,हैडलर के इशारे पर लगाई गई थी आग ● हैडलर को बड़े टारगेट के लिए खुद को साबित करना था

कोच्चि (एजेंसी)। केरलम के कोच्चि में ऐतिहासिक यहूदी सिनागॉग (प्रार्थनास्थल) के सामने 12 अक्टूबर को हुई आगजनी को पुलिस ने बड़े आतंकी साजिश का हिस्सा बताया है। पुलिस के मुताबिक, 32 साल के आरोपी एबिन पॉल ने यह आग लगाई थी। कोच्चि के पुलिस कमिश्नर कलिराज महेश कुमार ने कहा कि 12 अक्टूबर की सुबह किया गया हमला एक टेस्ट केस था। आरोपी को पहले कोच्चि में खुद को साबित करने के लिए कहा गया था। इसी के चलते पॉल ने पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद अपने मोबाइल पर घटना का वीडियो भी बनाया था।



परिवार ने कहा- डिप्रेशन का मरीज है पॉल

पॉल एर्नाकुलम जिले में कोलेनचेरी के पास पुथेनक्कुज के पास वदयाम्पडी का रहने वाला है। वह एक डिजाइन ग्रेजुएट है। पॉल के परिवार ने मुताबिक, वह डिप्रेशन का इलाज करा रहा था और घर से डिजाइन का काम भी करता था। पॉल अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में है। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन से फोरेंसिक रिजल्ट्स निकाले हैं, जिससे बैन आतंकवादी संगठन के हैडलर के बारे में और डिटल्स पता चली हैं। कमिश्नर ने कहा- फिलहाल हम और जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बड़े आतंकी साजिश से जुड़ी जानकारीयों की जांच की जा रही है।

बैलेट पेपर से हुए चुनाव, कांग्रेस कितनी सीटें जीती!

● **एमएलसी चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज**



बीजेपी काशी हारी,यूपी की 5 सीटें जीती- चार राज्यों की 28 एमएलसी सीटों के नतीजों में बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां भाजपा के पांच बार के एमएलसी नवल किशोर यादव समेत चार सिटिंग

एमएलसी चुनाव हार गए। जन सुराज ने दरभंगा शिक्षक सीट जीतकर विधान परिषद में खाता खोला। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 5 सीटों पर कब्जा किया, जबकि वाराणसी शिक्षक सीट सपा के खाते में गई।

केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का दीवाली गिफ्ट

डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ते (डीए) व महंगाई राहत को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार की ओर से दीवाली से पहले ही बड़ा गिफ्ट मिल गया है। देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी के साथ अब यह 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है। सरकार ने डीए और डीआर में बढ़ोतरी के लिए 7वें वेतन



6वें और 5वें वेतन आयोग वालों को भी राहत

सरकार ने 6वें और 5वें वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। ये बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। महंगाई भत्ते के अलावा कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी है। कटेनर मैयूफेक्चरिंग योजना- इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले को अपनाया है। इस बढ़ोतरी पर करीब 10,016 करोड़ रुपये खर्च होंगे। डीए और डीआर की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक के एरियर का भुगतान मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक 18,000 रुपये है तो उसे 60 फीसदी के हिसाब से 10,800 रुपये महंगाई भत्ता (डीए) मिल रहा था।

पायलट मच्छार को यूएई का बड़ा सम्मान

राष्ट्रपति ने गले लगाया,दुबई प्रिंस ने की तारीफ कहा-वे हमारी पहचान हैं, प्लेन क्रैश रोका था

अबू धाबी (एजेंसी)। यूएई ने फ्लाईदुबई की फ्लाइट को क्रश से बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को ‘जायद II- फर्स्ट क्लास’ से सम्मानित किया। इस दौरान UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मच्छर को गले लगाया। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने स्मित को अपने देश की पहचान बताया। जायद-II, UAE के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। फ्लाईदुबई फ्लाइट के पायलट मच्छर ने 30 सितंबर को प्लेन क्रैश कराने की कोशिश नाकाम कर दी थी। यह प्लेन दुबई से तेल अवीव जा रही था। इस दौरान को-पायलट ने उन पर हमला कर दिया था। राष्ट्रपति बिन जायद ने फ्लाइट के करू के सदस्यों को भी सम्मानित किया। इस दौरान UAE के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक

शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम भी मौजूद थे। UAE के नेताओं ने कैप्टन मच्छर और करू के सदस्यों की हिम्मत और जिम्मेदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में भी क्रू ने यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कैप्टन स्मित मच्छर ने हिम्मत, जिम्मेदारी और इंसानी जान की परवाह करने की मिसाल पेश की। हमें गर्व है कि वे हमारी टीम का हिस्सा हैं, हमारे देश की कहानी का हिस्सा हैं और, श्रु की पहचान का हिस्सा हैं। कैप्टन मच्छर जब चोटों का इलाज करा रहे थे, तब दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कैप्टन की हिम्मत और लोगों की जान बचाने के प्रयासों की तारीफ की थी।

को-पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला किया था

30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट स्न1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान विमान के को-पायलट ने कॉकपिट में कैप्टन मच्छर पर हमला कर दिया। हमले में कैप्टन घायल हो गए। उन्होंने बताया था कि को-पायलट ने सिर पर कई वार किए। को-पायलट ने विमान को गिराने की कोशिश में कैप्टन पर कॉकपिट में ही मौजूद इमरजेंसी कुल्हाड़ी से हमला किया था। इस दौरान मच्छर ने विमान से हार्डजैक का संकेत भी भेजा था।

भारत और अमेरिका के बीच बड़ा रक्षा समझौता

● **राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने की बातचीत**

मनीला (एजेंसी)। अमेरिका और भारत के बीच 10 वर्षों के लिए जो डिफेंस प्लान पिछले साल तैयार किया गया था उसकी समीक्षा की गई है। फिलीपींस के मनीला में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेमसेथ के बीच मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच 10 सालों के लिए डिफेंस फ्रेमवर्क में आए डेवलपमेंट की समीक्षा की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, सैन्य तकनीक और हथियारों के संयुक्त उत्पादन को लेकर बात की गई है। फिलीपींस के सेबू में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और नये क्षेत्रीय सुरक्षा



चुनौतियों को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल दोनों देशों के बीच इस डिफेंस फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए गये थे। इसका मकसद दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। यूएस-इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप पर पिछले साल 31 अक्टूबर को राजनाथ सिंह व हेगसेथ ने दस्तखत किए थे।

कर्नाटक- कांग्रेस हारी विपक्ष ने चारों सीटें जीतीं

कर्नाटक में एमएलसी की चार सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। विपक्षी जनता दल (सेक्युलर) यानी जेडीएस ने कांग्रेस से एक सीट छीन ली, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा ने अपनी तीनों सीटें बरकरार रखीं। बेंगलुरु शिक्षक सीट पर भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ रहे जेडीएस उम्मीदवार एपी रंगनाथ ने कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी पुट्टन्ना को 908 वोटों से हराया। पुट्टन्ना को 9,902 वोट मिले, जबकि रंगनाथ को 10,810 वोट मिले। उत्तर-पूर्व शिक्षक सीट पर भाजपा के मौजूदा एमएलसी शशिल जी. नामोशी ने कांग्रेस उम्मीदवार शरणप्पा मतूर को हराया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नामोशी ने इस सीट पर लगातार पांचवीं बार जीत दर्ज की है। नामोशी को 15,596 वोट मिले, जबकि मतूर को 12,299 वोट मिले।

भोपाल में 700 केजी एनालॉग पनीर जब्त

मुरैना से आ रहा था, ट्रेन से उतारते ही दबोचा

भोपाल। दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने भोपाल में बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर से 7 किंटल एनालॉग पनीर जब्त किया गया। यह ट्रेन के जरिए मुरैना से यहां लाया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार रात 2 बजे यह कार्रवाई की। 700 किलो से अधिक एनालॉग पनीर की कीमत 2.5 लाख रुपए है। विभागीय अधिकारियों ने बिल्टी और बिल के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई कर दी है। बुधवार सुबह तक कार्रवाई



जारी है। मग्न में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद यह पहली कार्रवाई है। जांच कर रही टीम अफसरों की टीम यह पता लगा रही है कि पनीर की सप्लाई कहाँ होने वाली थी? किस होटल, रेस्टोरेंट या डेवरी पर यह पनीर जाने वाला था। इसके बाद संबंधित के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे एमपी में प्रतिबंधित है एनालॉग पनीर करीब तीन महीने पहले सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया था। बता दें कि एनालॉग पनीर को असली दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें दूध की जगह या दूध के साथ वनस्पति वसा, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कम कीमत के कारण बाजार में इसकी खपत तेजी से बढ़ी है।

मानवाधिकार आयोग ने जताई थी नाराजगी

एनालॉग पनीर की बिक्री को लेकर तीन महीने पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने भी नाराजगी जताई थी। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों को पत्र लिखने का फैसला किया था। इसी बीच सरकार ने पूरे प्रदेश में इस तरह के पनीर पर रोक लगा दी थी। बावजूद भोपाल में 7 किंटल एनालॉग पनीर खपाने का मामला सामने आया है।

संपादकीय

अब चीतों का भी अवैध शिकार

अब मध्यप्रदेश में बाघों के बाद चीते भी अवैध शिकारियों के निशाने पर आ गए हैं। यह अपने आप में बेहद गंभीर और चिंताजनक बात है। क्योंकि जहां सरकार देश में चीतों की वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं उनके गैरकानूनी शिकार की कोशिशें भी बख़ीफ बढ़ रही हैं। ताजा घटनाक्रम मप्र के शिवपुरी जिले के कूनों अभयारण्य का है, जहां विदेश से भारत लाए गए चीतों में से एक मादा चीता निर्वा की 19 छर्छे लगने से मौत हो गई। यह गोलियां किसने चलाई, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन चीते के पोस्टमार्टम में 5 छर्छे मिले हैं। पूरे मामले की संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते जांच के लिए उच्चस्तरीय टीम भेजी है। इस टीम में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के वन महानिरीक्षक, वन्यजीव अपराध निंत्रण ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक और ब्यूरो के क्षेत्रीय उपनिदेशक शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी वन और पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि टीम अपनी जांच और सिफारिशें मंत्रालय को सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों के लिए आगे के निर्देश तय किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पुनर्वास योजना के तहत भारत लाए गए थे। ताजा घटना ऐसे समय हुई है, जब भारत में चीतों को फिर से बसाने की परियोजना के तहत उनकी संख्या बढ़ाने के साथ उनके संरक्षण और निगरानी पर साल 2022 से पहल शुरू की गई। इस घटना के बारे में मप्र की प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वाईन डॉ. संमिता राजौरा का कहना है कि केएनजी22 को 25 अक्टूबर को श्योपुर टैरिगेरियल फॉरेस्ट डिवीजन के कंपार्टमेंट नंबर 748 के इलाके में घायल हालत में पाया गया था। हमने पूरी कोशिश की उसे बचाने की। शुरूआती एक्स-रे में चीते के शरीर के अलग-अलग हिस्सों में कई फ़ोरैन ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए थे। इसके बाद उसका इलाज शुरू किया गया। चीते के शरीर से पांच फायरआर्म पैलेट यानी बंदूक के छर्छे निकाले गए। उन्होंने कहा कि इस घटना की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। अभी यह यह जांच का विषय है कि इस चीते का शिकार हुआ है या किसी ग्रामीण ने अपने पशुओं के बचाव में यह सब किया। राजौरा के मुताबिक हर चीते के पीछे एक मॉनिटरिंग टीम है जो लगातार रेंडियो कॉलर के सिग्नल के साथ चीते पर नजर बनाए रखती है। जांच दल इस बात की भी जांच करेगा कि मॉनिटरिंग टीम को गोली चलने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी और रेंडियो कॉलर के सिग्नल को ट्रैक करने में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। वैसे भी मप्र का कूनों, श्योपुर और भूरना के आसपास के जंगल पहले की तेंदुओं के कथित शिकार से जुड़ी जांच के केंद्र में रहे हैं। इस साल की शुरुआत में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, इलाके में तेंदुओं की हत्या और उनके अंगों की तस्करी से जुड़े कथित नेटवर्क की जांच की गई थी। इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। वन विभाग के मुताबिक, केएनजी22 की मौत के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या 58 रह गई है। इनमें 52 कूनों नेशनल पार्क, चार गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और दो वीरगंगा दुर्गावर्ति टाइगर रिजर्व में हैं। बहरहाल मादा चीते की हत्या के पीछे कारण भी हो, इसके लिए दोषी व्यक्ति को सख्त सजा दी जानी चाहिए। वरना अवैध शिकारियों के लिए मप्र बाघों की तरह चीतो का भी 'अभयारण्य' बन जाएगा।

युवा सक्रियता एवं राजनीतिक विशेषणों में उलझा लोकतांत्रिक संवाद

मुद्दा

डॉ. पी. के. बाजपेयी

लेखक समाज वैज्ञानिक हैं।

शब्द केवल शब्द नहीं होते। वे अपने साथ अर्थ, इतिहास और कभी-कभी राजनीतिक संकेत भी लेकर चलते हैं। ‘नक्सल’, ‘अर्बन नक्सल’ और अब ‘दिमागी नक्सल’ जैसे शब्द इसी श्रेणी में आते हैं। इनके इस्तेमाल ने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। सवाल यह है कि ‘दिमागी नक्सल’ किसी गंभीर सामाजिक-वैचारिक समस्या की ओर संकेत करता है या राजनीतिक विमर्श में असहमति रखने वालों को कठघरे में खड़ा करने का नया मुखवारा बन गया है?

आज इस बहस को समझने के लिए देश के विश्वविद्यालयों, नागरिक अधिकार आंदोलनों और युवाओं के बीच उठ रहे सवालों को भी देखना होगा। काक्रोच जनता पार्टी, आरक्षण हटाओ आन्दोलन और यूजीसी रोलबैक जैसे विरोध प्रदर्शनों ने यह दिखाया है कि नई पीढ़ी केवल सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने वाली पीढ़ी नहीं है; वह नीतियों, संस्थानों और अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर उतरने का साहस भी रखती है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के व्याख्यानों ने इस बहस को तेज किया है।

प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में बार-बार युवाओं, लोकतंत्र, विकसित भारत और नागरिक भागीदारी की बात करते हैं लेकिन जब युवा सवाल पूछते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं तो ऐसे युवाओं को राष्ट्र-विरोधी, अराजक या ‘दिमागी नक्सल’ कहकर खारिज कर दिया जाता है।

क्या असहमति अपराध है?

लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण असहमति को स्थान देना है। सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है। किसी नीति पर सवाल उठाना राष्ट्र-विरोध नहीं है। किसी कानून के प्रभाव पर चिंता व्यक्त करना, विस्थापितों अथवा आदिवासियों के अधिकारों की बात करना, पर्यावरण की रक्षा की मांग करना या मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रश्न उठाना अपने आप में नक्सली मानसिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। काक्रोच जनता पार्टी, आरक्षण हटाओ आन्दोलन और यूजीसी रोलबैक से जुड़े विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के सवालों और तौर तरीकों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है लेकिन उन्हें दिमागी नक्सल करार देना लोकतांत्रिक बहस को कमजोर करता है। किसी आंदोलन की आलोचना उसके तथ्यों, मांगों और तरीकों के आधार पर होनी चाहिए, न कि उसके प्रतिभागियों पर राजनीतिक लेबल लगाकर। भारत का संविधान नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लोकतंत्र इसलिए लोकतंत्र है क्योंकि इसमें सभी नागरिकों का एक ही विचार होना आवश्यक नहीं है। यदि ‘दिमागी नक्सल’ शब्द हर उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने लगे जो सरकार से असहमत है, विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछता है, किसी नीति के खिलाफ प्रदर्शन करता है या संस्थागत निर्णयों की समीक्षा की मांग करता है, तो यह शब्द समस्या को समझने के बजाय बहस को समाप्त करने का माध्यम बन जाएगा।

राजनीति में लेबल का आकर्षण

राजनीति में लेबल लगाना आसान होता है। इससे जटिल प्रश्नों को घुमाना आसान हो जाता है। किसी

व्यक्ति को ‘राष्ट्रवादी’ या ‘राष्ट्र-विरोधी’, ‘देशभक्त’ या ‘देशद्रोही’, ‘नक्सल’ या ‘गैर-नक्सल’ के खानों में रख देना बहस को आसान बना देता है।

एक व्यक्ति किसी सरकारी नीति का विरोध कर सकता है और फिर भी देश के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हो सकता है। कोई छात्र किसी विश्वविद्यालयी निर्णय की आलोचना कर सकता है और संविधान में गहरी आस्था रख सकता है। कोई सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी



अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है और नक्सलवाद का उतना ही विरोधी हो सकता है। काक्रोच जनता पार्टी और आरक्षण हटाओ आन्दोलन जैसे विरोध प्रदर्शनों को भी इसी व्यापक लोकतांत्रिक संदर्भ में समझना चाहिए। इन संगठनों की मांगों, भाषा और तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन उन्हें सीधे ‘दिमागी नक्सल’ कह देना न तो विश्लेषण है और न ही समाधान। इसी तरह यूजीसी रोलबैक के विरोध में उठे सवाल केवल किसी एक अधिसूचना या प्रशासनिक निर्णय तक सीमित नहीं हैं। वे शिक्षा की दिशा,

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, छात्रों की भागीदारी और नीति-निर्माण में पारदर्शिता से जुड़े प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर तर्क और संवाद से दिया जाना चाहिए।

युवाओं का पुनरुत्थान

हाल के वर्षों में युवाओं की सार्वजनिक भूमिका फिर से उभरती दिखाई दे रही है। विश्वविद्यालय परिसरों, नागरिक मंचों और डिजिटल माध्यमों से निकलकर युवा अब नीतिगत बहसों में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। वे रोजगार, शिक्षा, फीस, सामाजिक न्याय, संस्थागत स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं।

यह पुनरुत्थान केवल विरोध की राजनीति नहीं है। यह उस पीढ़ी की बेचैनी भी है जो अपने भाव्य को लेकर गंभीर है। वह पूछना चाहती है कि शिक्षा के बाद रोजगार कहीं है, संस्थानों में अवसर कितने समान हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है और नागरिकों की आवाज कितनी सुनी जाती है। युवा अब केवल परीक्षा, नौकरी और निजी जीवन तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे इतिहास, समाज, संविधान और सार्वजनिक नीति पर चर्चा करना चाहते हैं। यदि इस सक्रियता को ‘अराजकता’ या ‘दिमागी नक्सलवाद’ कहकर दबाया जाएगा, तो इससे समस्या समाप्त नहीं होगी; बल्कि युवाओं और संस्थानों के बीच अविश्वास बढ़ेगा।

एक बेरोजगार युवा के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि उसे रोजगार मिलेगा या नहीं। एक छात्र के लिए यह

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की थी। इंदिरा गांधी और उनके बाद राजीव गांधी की सरकार ने मंडल आयोग की इन सिफारिशों को लागू नहीं किया था। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की। इसके बाद 2019 में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया।

असल में आरक्षण का उद्देश्य पिछड़े, शोषित और वंचित वर्गों को सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षण संस्थानों और विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के स्तर पर ओबीसी को 27 फीसदी, एससी को 15 फीसदी, एसटी को 7.5 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न संशोधनों और प्रावधानों के अनुसार कुल केंद्रीय आरक्षण 59.50 प्रतिशत है। वहीं ओबीसी और कुछ श्रेणियों में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को इस दायरे से बाहर रखने के लिए क्रीमी लेयर का नियम लागू है, जिसकी वर्तमान में सीमा आठ लाख रुपए वार्षिक आय है। वहीं इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की थी। हालांकि केंद्र सहित तमिलनाडु व छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों ने 69 प्रतिशत तक आरक्षण देकर विशेष कानूनों के तहत इस सीमा को पार किया है।

असल में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट एवं राज्य न्यायालयों की टिप्पणियां गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करती हैं। इससे पता चलता है कि आरक्षण की वजह से कितनी पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो आरक्षण अपने उद्देश्य में असफल रहा है। असल में अब आरक्षण की समीक्षा नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह समाप्त किया जाना जरूरी है। न यह जाति के आधार पर हो और ना ही आर्थिक आधार पर। किसी भी तरह के आरक्षण की अब कोई जरूरत नहीं है। इसकी जगह हर जाति और वर्ग के गरीब छात्रों को पूरी तरह निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें पढ़ा-लिखाकर योग्य बनाया जाए। आरक्षण से बनने वाले नेता और कर्मचारियों को देश देख ही रहा है। दुनिया में कहीं पर भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो फिर हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था को क्यों लागू किया गया है? देश को कमजोर होने से बचाने के लिए आरक्षण को पूरी तरह हटाना जरूरी है। देश पहले है, जातियां और बाकी सब कुछ उसके बाद।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशन एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंध परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जेन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

मुकेश राठौर

लेखक व्यंग्यकार हैं।

पति द्वारा लंबी उमर करवाने के बदले अपनी सगी पत्नी को उपहार स्वरूप साड़ी दिलाने की परम्परा कब शुरू हुई ये तो पक्के से नहीं पता लेकिन इतना तो तय है जबसे करवा चौथ शुरू हुई साड़ी देने का रिवाज भी कदाचित्त उसी समय से शुरू हुआ होगा! साड़ी है गर सिक्के,मुर्ति या बर्तन होते तो पुरातत्ववेत्ता अब तक नदियों के किनारे खोद कर कर बता चुके होते। खैर, करवा चौथ पर पति से और रक्षाबंधन पर भाई से साड़ी प्राप्त करना हर महिला के मौलिक अधिकार जैसा है। साल के बारह महीनों में दो साड़ी तो पक्की समझिये,इस बीच ससुराल या मायके में कोई शुभ प्रसंग आ जाए तो यह आंकड़ा दो से दस हो जाए फिर भी बस कहने का सवाल ही नहीं। पहनने योग्य कपड़ों का व्यापक सर्वे किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं देश में साड़ियां,पतलून-कमीज से इक्कीसी बल्कि बत्तीसी बैठेगी।

कुल जमा मसला यह कि सिर पर खड़ी करवा चौथ देख हम साड़ी खरीदने शहर गए। उन्हें साड़ी लाने तो मुझे गाड़ी च-लाने के लिए जाना ही था। यूं तो बाजार

करवा चौथ और साड़ी को लेकर किंकर्तव्यविमूढ़ सिरीमती

में साड़ियां ही साड़ियां थी मगर हमें तो बॉम्बे बाजार स्थित 'पहली पसंद' साड़ी शोरूम पर जाना था क्योंकि उसका नाम चलता है। एक बार किसी का नाम चल जाए तो फिर काम कौन देखता है! देखा तो पाया शोरूम में पृष्ठ भाग तो दूर पैर रखने कि जगह नहीं थी,बाहर पार्किंग के हाल भी इससे जुदा न थे। सिरीमती को शोरूम में छोड़ सोचा अभी दस बज रही है इधर बैठे-बैठे क्या करूंगा! कॉलोनी वाली मैडम फोन पर बार-बार प्लॉट देखने का आग्रह करती रहती है आज मौका है और मजबूरी भी। मैं प्लॉट देखने निकल पड़ा। मात्र हजार रूपये जमा करते ही प्लॉट बुक हो गया। फाइनंसेर भी घात लगाकर हमला करने को तैयार बैठे थे।वताने पर कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं,अतिथि नहीं फिक्समफिक्स तिथि प्रजाति का। फिर क्या था, उन्होंने अठारह लाख फाइनंसेर की प्रक्रिया अब्रूड मुहूर्त में कर डालीं। सरकारी कर्मचारी को लोन देने से भला कौन मना करेगा! सरकारी आदमी चाँद पर घर बनाना चाहे तो लोन देने वाले मौका देखे बगैर चौका जमा दें। हां कोई गरीब कुटी चाहे तो दो जोड़ी चप्पल घिस जाए। आप सोच रहे होंगे सरकारी आदमी पर इतनी मेहरबानी किसलिए? वह इसलिए कि उसके पैसे को मर नहीं

होती,वह मर भी जाए तो भी। वे बोलें सर आज से आप यहां के जमींदार हुए। आपको किस्ती की भी चिंता नहीं,बारह लाख के प्लाट के लिए पंद्रह हजारि दस सालों की किस्त और बात खतमा। यकीन मानिये मालूम भी नहीं पड़ेगा। कर्ज किस्ती में चुकाया जाए तो मालूम नहीं पड़ता,फिर बारह के बदले अठारह चले जाए अलग बात है। इधर का काम निपटा तो उप पंजीयक के सामने उपस्थित होकर प्लॉट की रजिस्ट्री भी सम्पन्न करवा लीं। हालांकि इधर लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि सरकारी काम समय मांगता है लगे तो सेवा भी।

बहरहाल,आप थे हरि भजन को ओटन लगे कपास वाली स्थिति से बाहर निकलते ही मुझे सिरीमती की याद आई हालांकि प्लॉट खरीदी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान उनकी याद आती बल्कि सताती रही। याद ही आ सकती थीं कॉल नहीं क्योंकि उनके पास मोबाइल भी तो नहीं था। अब मैंने पहली फुर्सत में पहली पसंद की राह पकड़ी। चलती बाइक पर विचारता रहा करवा चौथ पर उनके द्वारा अपने चाँद को देखने से पहले आज मेरे द्वारा अपने चांद को देखना भयंकर अनुभव रहेगा। पता नहीं बेचारी कहाँ किस हाल में 'आ जा रे मैं तो कबसे खड़ी इस पार,ये आखियां थक गई पंथ निहार' गुनुगुना रही

होगी।एक बार लगा शोरूम में बोर होते-होते सिरीमती कहीं किराये से रह रही बोरगांव बुजुर्ग वाली साली साहिबा के घर पैदल ही तो नहीं पहुंच गईं।मैं सीधे वहीं पहुंचा,वो वहां नहीं थीं। ऐसा तो नहीं अपने मामाजी के घर बैठी हों। या फिर मेरी मौसी के घर।नहीं..नहीं...सगी बहन के ऊपर सास की बहन को तरजीह सम्भव ही नहीं। मामाजी से फोन पर पता करने पर पता चला वो नहीं आई। इस पूछ परख में शाम होने को आई। अब मेरे मन में भावी अनिष्ट की आशंका गहराने लगी। सोचा इस तरह धुपल में लड़ु चलाने के बजाय पहली पसंद पर ही पहले जाया जाए वहीं से खुलेगा कोई रास्ता। सारे किन्तु-परन्तु मन में लिए मैं वही पहुंचा जहां सुबह उन्हें छोड़ कर आया था। मैंने काउंटर पर बैठे सेठ टाइप आदमी से पूछा सुबह हमारी सिरीमती इधर आई थी साड़ी लेकर यहां से कब निकली? 'आई साहब मैडम जी तो अभी इधर ही है' उसने कहा। महिलाओं की भीड़ में मेरी नजर अपनी महिला पर गई। वो दो साड़ियां हाथ में लिए मेरी ओर लपकी बोलीं बस हो ही गया,ये बताओ इन दो में से कौन सी मुझ पर अच्छी लगेगी। अब मेरा मन प्लॉट का नामांतरण करवाने का होने लगा, मगर कार्यालयीन समय इजाजत नहीं दे रहा था।

दृष्टिकोण

संध्या अग्रवाल

लेखक साहित्यकार हैं।



विरोध प्रदर्शन जीने के अधिकार का हिस्सा है और लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। इस देश में विरोध-प्रदर्शन हमेशा होते रहे हैं और उनके लिए पूरा अवसर भी रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक, कई बड़े बदलावों की शुरुआत किसी न किसी आंदोलन से ही हुई है। इसलिए विरोध के अधिकार पर कोई प्रश्न नहीं उठाना जा सकता; वह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। दिल्ली के कर्नाट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को बंद रखने तथा वहाँ प्रस्तावित तिरंगा मार्च के संदर्भ में छोटे व्यापारियों की आजीविका का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। 16 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने छोटे दुकानदारों, फेरीवालों और उनके परिवारों की कठिनाइयों पर चिंता जताई। अदालत ने यह भी कहा कि यदि प्रतिबंधों के कारण व्यापारियों को अनुचित नुकसान पहुँचता है और कार्रवाई गैरकानूनी पाई जाती है, तो मुआवजे सहित उचित कदम उठाए जा सकते हैं। यह प्रसंग एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है—जब दो लोकतांत्रिक अधिकार आमने-सामने आ जाएँ, विरोध का अधिकार और रोज़ी-रोटी का अधिकार, तो उनके बीच संतुलन कैसे बने?

किसी राजनीतिक दल या संगठन के लिए आंदोलन अपनी माँगों को सामने रखने और जनसमर्थन जुटाने का माध्यम हो सकता है। नेताओं के भाषण होते हैं, नारे लगते हैं और समाचार माध्यमों में चर्चा होती है। लेकिन इसी दौरान सड़क किनारे दुकान लगाने वाले व्यक्ति, छोटी दुकान के मालिक, रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूर किस स्थिति से गुजरते हैं, इस पर भी ध्यान देना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। उनके लिए आंदोलन के दौरान कामकाज प्रभावित होने का अर्थ उस दिन की कमाई का नुकसान हो सकता है, जिससे परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं।

त्योहारों के समय यह प्रश्न और गंभीर हो जाता है। मिठाई की दुकान, कपड़ों का छोटा प्रतिष्ठान, मिट्टी के दीपक बेचने वाला कुम्हार और फूलों की दुकान लगाने वाला विक्रेता—इन दिनों की बिक्री पर उनकी आय का बड़ा हिस्सा निर्भर कर सकता है। यदि रास्ते बंद हों, यातायात बाधित हो या बाजार तक ग्राहक न

आंदोलन का अधिकार और आम आदमी की रोज़ी

त्योहारों के समय यह प्रश्न और गंभीर हो जाता है। मिठाई की दुकान, कपड़ों का छोटा प्रतिष्ठान, मिट्टी के दीपक बेचने वाला कुम्हार और फूलों की दुकान लगाने वाला विक्रेता—इन दिनों की बिक्री पर उनकी आय का बड़ा हिस्सा निर्भर कर सकता है। यदि रास्ते बंद हों, यातायात बाधित हो या बाजार तक ग्राहक न पहुँच पाएँ, तो नुकसान केवल एक दिन की बिक्री तक सीमित नहीं रहता। इसका असर परिवारों के घरेलू बजट, कर्मचारियों की मजदूरी और छोटे कारोबार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। यहाँ यह स्पष्ट रहना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी नागरिक को अपनी माँग रखने, प्रशासन से प्रश्न पूछने या सरकार के निर्णय से असहमति जताने के कारण गलत नहीं ठहराया जा सकता।

पहुँच पाएँ, तो नुकसान केवल एक दिन की बिक्री तक सीमित नहीं रहता। इसका असर परिवारों के घरेलू बजट, कर्मचारियों की मजदूरी और छोटे कारोबार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। यहाँ यह स्पष्ट रहना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी नागरिक को अपनी माँग रखने, प्रशासन से प्रश्न पूछने या सरकार के निर्णय से असहमति जताने के कारण गलत नहीं ठहराया जा सकता। कई बार आंदोलनों ने वास्तविक समस्याओं को सामने लाने और समाधान का रास्ता खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए हर आंदोलन को अनावश्यक या जनविरोधी कहना उचित नहीं होगा। प्रश्न आंदोलन करने के अधिकार का नहीं, बल्कि इस बात का है कि उसे किस तरह प्रभावी, शांतिपूर्ण और दूसरों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

जब किसी प्रदर्शन से सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका हो, तब उसके आयोजकों और प्रशासन को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे विरोध की आवाज भी प्रभावी ढंग से उठ सके और आम नागरिकों की कठिनाइयाँ भी कम हों। जहाँ सड़क पर प्रदर्शन आवश्यक हो, वहाँ मार्ग, समय, यातायात और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था पहले से तय की जा सकती है। आयोजक यदि अपने समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने की अपील करें तथा



करने, यातायात चलाए रखने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों, दोनों को चोटें आती हैं। ऐसी घटनाओं में केवल एक पक्ष की पीड़ा देखना पर्याप्त नहीं है। यह भी जाँचना चाहिए कि टकराव कैसे शुरू हुआ, बातचीत के क्या प्रयास किए गए, बल प्रयोग की आवश्यकता कितनी थी और क्या उसका इस्तेमाल निधारित सीमाओं के भीतर हुआ। जवाबदेही

का सिद्धांत सभी पक्षों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

राजनीतिक आयोजनों में एक और प्रश्न उठता है—आंदोलन का उद्देश्य क्या है और उसका परिणाम क्या निकला? क्या उससे किसी समस्या का समाधान हुआ, संबंधित पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी या प्रभावित लोगों को राहत मिली? आयोजकों से उनके तरीकों और प्राप्त परिणामों के बारे में प्रश्न पूछना लोकतांत्रिक जागरूकता का हिस्सा है। ऐसा करना अपने आप में आंदोलन के अधिकार का विरोध नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य और प्रभाव को समझने का प्रयास है। किसी की मंशा पर बिना प्रमाण आरोप लगाने से बचना भी उतना ही आवश्यक है।

नुकसान की भरपाई का प्रश्न भी गंभीरता से विचारणीय है। छोटे दुकानदार या दिहाड़ी मजदूर के पास इतना आर्थिक सहारा नहीं होता कि वह कई दिनों की कमाई खोने के बाद सहजता से अपना काम फिर शुरू कर सके। इसलिए जिन परिस्थितियों में कानून और न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत मुआवजे की जिम्मेदारी तय हो सकती है, वहाँ प्रभावित व्यक्ति को केवल नुकसान सहने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। साथ ही, आयोजनों की अनुमति देते समय प्रशासन को व्यापारियों, स्थानीय निवासियों और आम नागरिकों की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए।

लोकतंत्र केवल अपनी बात कहने की स्वतंत्रता का नाम नहीं है; यह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी भी है। जिस नागरिक को विरोध करने का अधिकार है, उसी नागरिक को निर्बाध आवागमन, सुरक्षित वातावरण और अपनी आजीविका चलाने का अधिकार भी है। इन अधिकारों को एक-दूसरे का विरोधी बनाने के बजाय उनके बीच संतुलन स्थापित करना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की कसौटी है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह शांतिपूर्ण विरोध के लिए उचित व्यवस्था बनाए, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और सामान्य जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने का प्रयास करे।

लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध केवल असहमति व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं को सार्वजनिक विमर्श तक पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण अधिकार भी है। इस अधिकार की रक्षा करते हुए सामान्य नागरिकों की आजीविका और सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। सरकार, प्रशासन, आंदोलन के आयोजकों और नागरिकों के बीच संवाद तथा सहयोग से ऐसा संतुलन बनाया जा सकता है, जिसमें विरोध की आवाज भी सुनी जाए और किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों।

अंततः आंदोलन की सफलता केवल भीड़ के आकार, नारों की गूँज या समाचारों में मिली जगह से नहीं मापी जानी चाहिए। उसका मूल्यांकन इस बात से भी होना चाहिए कि उसने समस्या के समाधान में कितना योगदान दिया और आम नागरिकों को कितनी कीमत चुकानी पड़ी। लोकतंत्र में आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन उस आवाज के साथ जिम्मेदारी का स्वर भी सुनाई देना चाहिए। क्योंकि किसी भी आंदोलन में जनता का हित महत्वपूर्ण है और विरोध का अधिकार तथा रोज़ी-रोटी का अधिकार, दोनों एक साथ सुरक्षित रहने चाहिए।

विश्व राजनीति

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।



देश छोटा है; चैतरफा अन्य देशों के भूखंडों से घिरा हुआ यानि भूआवेष्टित। आबादी तकरीबन पैंसठ लाख। इतिहास के थपेड़ों के बीच मानचित्र में उभरे इस योरोपीय राष्ट्र में युवकों ने कमाल कर दिखाया। चौदह सालों से जमे-जमाये कठोर और सुदृढ़ निजाम को उखाड़ फेंकना आसान न था, लेकिन छात्रों ने अपनी एकजुटता, संघर्षशीलता और आंदोलनधर्मिता से संसदीय चुनावों में सर्वथा नयी इबारतें लिखीं। फलतः स्टूडेंट्स-लिस्ट के उम्मीदवारों के लिये संसद में प्रवेश और सरकार के गठन के द्वार खुल गये। छात्रों की चुनौती अपनी जगह थी, लेकिन राजनीतिक पंडितों को यह यकीन न था कि छात्र समूहों द्वारा चुने हुये समाज के विभिन्न तबकों-अध्यापकों, डॉक्टरों, श्रमिकों और इंजीनियरों आदि के गैर पेशेवर उम्मीदवार वर्कर्स पार्टी के पेशेवर प्रत्याशियों को धूल चटा देंगे।

मगर ऐसा हुआ और उके की चोट पर हुआ। सर्बिया में क्रांति बंदूक की नली से नहीं, वरन मतपेटियों से निकली। प्रतिरोध की जीत हुई और सत्ता की हार। यह कू-दे-ता नहीं था। निरंकुश, दमनकारी और भ्रष्ट सत्ता हारी और शांतिप्रिय, परिवर्तनकारी और अहिंसक सत्याग्रही जीती। यह भारत से हजारों मील दूर एक छोटे से योरोपीय राष्ट्र की परिघटना है। देश छोटा है, किंतु संदेश बड़ा 56 वर्षीय राष्ट्रपति अलेक्सान्द्र बुचिश के हाथों से अब सत्ता फिसल चुकी है। जनादेश ने छह फुट पांच इंच लंबे चरमोश बुचिश का कद छोट दिया है। अब वह निवर्तमान या भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैं। तय है कि उनकी

करतूतों की जांच होगी, उन पर मुकदमा चलेगा और उन्हें और उनके सहयोगियों को सजा भी मिलेगी। जनादेश इतना स्पष्ट था कि उन्होंने सारे चुनाव परिणाम घोषित होने से पेशगी ही अपनी हार कबूल कर ली। 250 सांसदों के सदन के नतीजों के ऐलान के अधबीच में ही बुचिश ने कहा - 'जाहिर है कि हमने यह चुनाव गँवा दिया है।'

सर्बिया के साथ जातीय संघर्ष, नरसंहार और विनाश की दारुण-गाथा जुड़ी हुई है। यूगोस्लाविया के के विघटन के बाद बाल्कन क्षेत्र में विपदाओं की बाढ़ आ गयी। ऐसे में सन 2006 में सर्बिया स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में मानचित्र पर उभरा और बीस सालों के गणतांत्रिक इतिहास में चौदह साल सत्ता की बागडोर बुचिश के हाथों में रही। दरअसल, बुचिश एक महत्वाकांक्षी, धूर्त और अनुदार राजनेता हैं। उन्होंने 23 वर्ष की वय में राजनीति में कदम धरे और अति उग्रवादी सर्बियन रेडिकल पार्टी ज्वाइन की। सन्



2008 में उन्होंने तोमिस्लाव निकोलस के साथ सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी की स्थापना की। सन् 2012 से 2023 तक वह इसके अध्यक्ष रहे। सर्बियन रेडिकल पार्टी के सांसद की हैसियत से कानून में स्नातक बुचिश सन 1998 में सूचना मंत्री बने तो पूत

के पांव पालने में दिख गये। वह 2000 में स्लोबोदान मिलोशेविच के पतन तक इस पद पर रहे और उन्होंने पत्रकारों पर कई दमनात्मक कानून थोपे और विदेशी टीवी चैनलों पर पाबंदी लगा दी। उनका दमन और उरपीड़न का निरंकुश रवैया मुसलसल जारी रहा। सन् 2012 में वह उपप्रधानमंत्री बने और 2014 में पीएम। सन् 2017 और फिर 2022 में वह राष्ट्रपति चुने गये। इसी साल पीएम बनने के मकसद से उन्होंने

इस्तीफा देकर चुनाव का दाँव खेला और स्टूडेंट लिस्ट के हाथों मुंह की खाई। बुचिश के पतन का कारण बनी एक नवंबर 2024 को नोवी साद रेलवे स्टेशन की दुर्घटना। कैनोपी गिरने से 16 लोगों की मौत के हदसे ने छात्रों को भड़का दिया। भ्रष्टाचार, नागरिक अधिकारों के

हनन और संस्थानों के राजनीतिकरण के मुद्दों से आंदोलन को विस्तार और बल मिला। नवकुबेर मिरोस्लाव मिस्कोविच की पुत्र माकों के साथ भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी, रिहाई और सरकार द्वारा हर्जाना देने के प्रसंग को अवाम ने स्वांग माना। बुचिश की घृणित मानसिकता का परिचय सेब्रेनिका कल्लेआम के बाद तब मिला, जब उन्होंने कहा - किल वन सर्व, वी विल किल हंड्रेड मुस्लिम्स।' जाहिर है कि वह इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं और उनके भीतर एक कातिल विद्यमान है। दमन-उरपीड़न के चलते उनके राजकाल में सर्बिया में भारी विदेशी निवेश, जोडीपी में वृद्धि और सफल विदेश नीति के दावों का मतदाताओं पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने स्टूडेंट लिस्ट को भरपूर समर्थन दिया। यूं तो छात्रों ने नेतृत्व किसी एक हाथ में नहीं था, अलबत्ता नोवी साद में मेडीसिन के प्रोफेसर एलिजा स्वदनोविच ने उन्हें बखूबी हाइड किया। बुचिश ने आंदोलनकारी छात्रों को 'ब्लाकेडर्स की संज्ञा दी, लेकिन नागरिकों के असंतोष और रोष की वाणी बनकर उभरे। छात्रों के नारे या सर्बिया, या माफिया, ज्ञान शक्ति है और सर्बिया हमारे साथ बढ़ रहा है, काम कर गये। अवाम ने निजाम बदलने के ध्वजवाहकों का साथ दिया। नतीजा सामने है। बेलोड और सर्वत्र अपूर्व जश्न का माहौल। इतिहास से सबक नहीं लेने वाले बुचिश ध्वशायी हो गये। देखना दिलचस्प होगा कि संकटों के दौर से गु्र रहे दुनिया के देश सर्बिया के सबक से क्या सबक लेते हैं?

समीक्षा

विजय जोशी

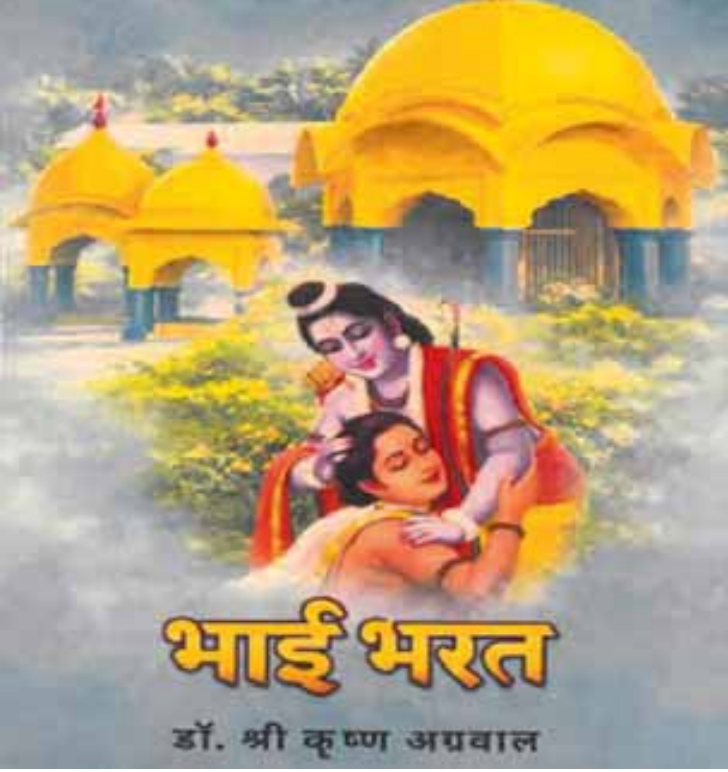
लेखक भेल भोपाल के पूर्व समूह महाप्रबंधक हैं।



कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्थात् हे प्राणी तू मात्र कर्म कर फल की आकांक्षा से रहित, क्योंकि फल की चाहत कर्म की पवित्रता को भंग कर देती है। कामनारहित कर्म उसे उसे एक नई ऊँचाई प्रदान कर देता है। यह कहा था कृष्ण ने द्वारप में पर भरत ने तो इसे एक युग पूर्व त्रेता में ही सिद्ध कर दिया था। यह शाश्वत सत्य खुलकर निखरा है एन.आई.टी. के. पूर्व प्रोफेसर डॉ. श्रीकृष्ण अग्रवाल की सद्य प्रकाशित पुस्तक 'भाई भरत' में। संक्षिप्त सार की एक बागनी। त्रेता में भरत उस निर्गुण उपासना के प्रतीक हैं, जिसमें उनकी घनीभूत पीढ़ा भक्ति का अवलंबन ले उसे समाज के समक्ष रचनात्मक स्वरूप प्रदान करती है, जिसे राम ने यूँ बखान किया : भरत अमित महिमा सुनु रानी जानहि रामु न सकहि बखानी राजनीति के संदर्भ में वे सुनीति के जीवंत स्वरूप हैं, न कि कूटनीति के। आज जहां लोग कानून की कमियाँ ढूंढकर अधर्म का सहारा लेते हैं वहीं भरत अपनी मां के अनर्थ का उत्तरदायित्व

भरत: अनासक्त कर्मयोग के आदर्श

स्वयं पर वहन कर सच्चे हृदय से करते हैं पश्चाताप तथा प्रायश्चित। सर्वप्रथम उनका नामकरण संस्कार ही कालांतर में उनकी पहचान बना : बिस्व भरन पोषन कर जोई ताकर नाम भरत अस होई सोचिये तब राम भरत दोनों भ्राताओं का निर्मल निश्छल प्रेम कितना अद्भुत और अलौकिक रहा होगा। राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे भरत तब भ्रात प्रेम में इस तरह डूबे हुए थे कि कह उठे : मोहि राजु हटि देखहु जबहीं रसा रसातल जाइहि तबहीं राम को लौटा लाने के प्रयास में सुमंत निषादराज आदि सबके आग्रह के बावजूद राम के कष्ट की अनुभूति सहेजे उन्हें स्मरण करते हुए वे पैदल ही चले : रामु पयोदेहि पायँ सिधाए हम कहँ रथ गज बाजि बनाए अर्थात यह स्वयंसिद्ध है कि धर्म



की आत्मानुभूति के साथ ही सेवा धर्म के भी प्रतीक हैं भरत: सबतें सेवक धरमु कठोरा। राम के अयोध्या के पुनारागमन का कोई नैतिक विकल्प ही दृष्टिगत ही नहीं था यानी पिता की आज्ञा का उल्लंघन एवं अवतार उद्देश्य की विफलता। तब भरत ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को स्वीकार किया और राम की चरण पादुका शिरोधार्य करते हुए राजसी वस्त्र त्याग नंदीग्राम में पर्णकुटी को स्थायी निवास बना शेष जीवन सहर्ष स्वीकार किया। इस धर्माचरण युक्त प्रसंग को लेखक ने कुछ यूँ संग्रहित किया है : बड़ों की आज्ञा का अनुपालन - अपराध स्वीकारोक्ति बजाय दूसरों पर थोपने के - ध्येय की साधना में तन्मयता - योग्यता के बावजूद दंभ से सर्वथा परे - अन्य की पीड़ा की स्व में

अनुभूति - पादुका स्वीकार कर विवाद को समाधान से सुलझाया कैकेयी प्रसंग : अगले प्रसंग में कैकेयी की अंतर्दशा की व्याख्या समाहित है, जिनका राम पर आगाध स्नेह था, किंतु अवतार उद्देश्य की पूर्णता हेतु उन्होंने अपमान की घनीभूत पीड़ा को सहकर भी सबसे दुष्कर कार्य का संपादन किया। यही कारण था कि राम चित्रकूट में सर्वप्रथम उन्हीं से मिले : प्रथम राम भेंटी कैकेई सरल सुभायँ भगति मति भेई और इसी तर्ज पर लंका विजय पश्चात जब लौटे तो सबसे पहले कैकेयी निवास ही पहुंचे : प्रभु जानी कैकई लजानी प्रथम तासु गृह गए भवानी रामकथा अद्भुत और अलौकिक है। कोई उच्च तकनीकी पायदान तक पहुंचा व्यक्ति इतनी गहराई से अनासक्त ऊर्मी भरत की संवेदनशीलता को कागज पर उकेर सके तो यह बात अपने आप में विलक्षण हो जाती है। यह करिश्मा किया है मेरे कॉलेज सहपाठी मित्र डॉ. अग्रवाल ने। सो वे बधाई के पात्र हैं। प्रकाशन एवं मुद्रण उत्तम। मुखपृष्ठ प्रभाव युक्त।

सीईसी सदस्य श्री सुनील लिमाये ने दिए निर्देश

चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन रोकने तीनों राज्यों के अधिकारी मिलकर करें प्रभावी कार्रवाई

16 वन चौकियां स्थापित होंगी, सप्ताह में दो बार संयुक्त जांच और हर तीन माह में अंतरराज्यीय बैठक; कैमरों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टावर से होगी निगरानी



पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करें। उन्होंने निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 16 वन चौकियां स्थापित करने, चंबल नदी क्षेत्र में कैमरों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टावर से निगरानी करने तथा नियमित संयुक्त जांच करने पर जोर दिया। साथ ही, अवैध उत्खनन से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों का परस्पर आदान-प्रदान करने और प्रत्येक तीन माह में अंतरराज्यीय बैठक में की गई कार्रवाई, निगरानी व्यवस्था और अवैध गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में ग्वालियर के मुख्य हथियार भी दिए गए हैं, जिससे वन संरक्षक श्री लोवित भारती, कलेक्टर मुरैना श्री लोकेश कुमार जागिड़, कलेक्टर भिण्ड श्री पवन जैन, श्योपुर कलेक्टर के प्रतिनिधि, कलेक्टर धौलपुर श्री बी.टी. श्रीनिधि, भरतपुर के मुख्य वन संरक्षक श्री पी. कथिरवेल, पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री धर्मराज मोणा,

पुलिस अधीक्षक भिण्ड श्री सूरज वर्मा, पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान, वन मंडलाधिकारी मुरैना श्री हरिशचन्द्र बघेल तथा आगरा ईस्ट के पुलिस उपायुक्त श्री अभिषेक अग्रवाल सहित मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, धौलपुर एवं आगरा के खनिज विभाग के अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा पुलिस, वन एवं राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 16 वन चौकियां स्थापित कर अवैध गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर श्री लिमाये ने निर्देश दिए कि चंबल नदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर निगरानी के लिए मुरैना वन मंडल द्वारा 16 वन चौकियां स्थापित की जाएं। मैदानी अमले को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर कार्रवाई प्रभावी बनाई जाए। वन विभाग को अतिरिक्त अमला उपलब्ध कराने के साथ आवश्यक संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जा सके। कैमरों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टावर से होगी निगरानी चंबल नदी क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था नियमित बनी रहे और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो।



कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में ए. पी. सी. की समीक्षा बैठक आयोजित

अशोक नगर (निप्र)। सोमवार को कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के. सी. गुप्ता की अध्यक्षता में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ए. पी. सी. की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों के लिए पानी, बीज एवं खाद की उपलब्धता के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों से जिले में कृषि कार्यों के लिए पानी की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण बीजों की व्यवस्था तथा किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिये। एपीसी श्री के सी गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को कृषि कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पानी, बीज एवं खाद की उपलब्धता बनाए रखने तथा इनकी आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। नरवाई में आग लगाने की

जन सुनवाई के दौरान सुनी आधा सैकड़ से अधिक आवेदकों की समस्याएं

दतिया (निप्र)। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु आज मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित की गई। आयोजित जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर श्री भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए आधा सैकड़ आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिए निर्देशित किया। अनिराकृत आवेदनों के लिये समय-सीमा निर्धारित कर अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान सीईओ जिला जिला पंचायत श्री शैलेंद्र सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

महर्षि वाल्मीकि जयंती पर करीला में समरसता सम्मेलन आयोजित

जनजाति आयोग के सदस्य श्री बरालाल अहिरवार ने की सहभागिता, सामाजिक समरसता और एकता का दिया संदेश

अशोक नगर (निप्र)। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के पावन अवसर पर अशोकनगर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल करीला में सोमवार को समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जनजाति आयोग के सदस्य श्री बरालाल अहिरवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में सहभागिता कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया तथा महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन, उनके आदर्शों और समाज को दिए गए अमूल्य योगदान को स्मरण किया। श्री अहिरवार ने कहा कि आज हमारे संपूर्ण भारत वर्ष में महर्षि बाल्मीकि जयंती आयोजित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि समरसता सम्मेलन का उद्देश्य समाज में आपसी सद्भाव, भाईचारे, समानता और एकता की भावना को मजबूत करना रहा। इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन दर्शन और उनकी शिक्षाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया। उनके आदर्श समाज को सत्य, सदाचार, कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय मूल्यों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु युवाओं को स्वरोजगार जोड़े



जाने के लिये जागरूक करना होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुगवली विधायक श्री बुजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी महान रचना रामायण के माध्यम से भारतीय संस्कृति, नैतिकता और आदर्श जीवन मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाया। उनका जीवन और कृतित्व समाज को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उनकी जयंती पर आयोजित इस प्रकार के सम्मेलन सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करने तथा

विभिन्न वर्गों के बीच परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर महंत श्री नारायण दास जी, सपना नहरिया, नरेश बालू, जितेन्द्र नहरिया, प्रकाश नहरिया, रवि मोहन, सहित समाजसेवी, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

मातृत्व और कर्तव्यनिष्ठा की अनूठी मिसाल

पटवारी श्रीमती संध्या शर्मा का मातृत्व और शासकीय दायित्व निर्वहन में संतुलन

शिवपुरी (निप्र)। आज के दौर में महिलाएं घर और बाहर दोनों मोर्चों पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभा रही हैं। ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं शिवपुरी जिले के पटवारी हल्का डोंगर (क्रमांक 122) में पदस्थ श्रीमती संध्या शर्मा। वह एक तरफ जहाँ शासन की महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना पंजीयन कार्य के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मात्र दो वर्ष के अपने छोटे से बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल रही हैं। एक तरफ जहाँ बच्चे की देखभाल वहीं दूसरी तरफ शासकीय स्वामित्व योजना के अंतर्गत जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करना और पंजीयन जैसे तकनीकी व जिम्मेदारी भरे कार्य समय पर पूरे करने होते हैं। श्रीमती संध्या शर्मा अपने दो साल के बच्चे को साथ लेकर अपने क्षेत्र में ड्यूटी पर पहुंचती हैं। उनके पति भी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, जिससे पारिवारिक व्यस्तताएं और बढ़ जाती हैं, परंतु इसके बावजूद वे कार्य के प्रति गंभीर हैं। श्रीमती संध्या शर्मा अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर क्षेत्र में पहुंचती हैं तथा स्वामित्व योजना से संबंधित भूमि अभिलेख तैयार करने और पंजीयन संबंधी कार्यों का निर्वहन करती हैं। उनके पति भी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में पारिवारिक एवं शासकीय दायित्वों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अपने कार्य के प्रति गंभीर हैं। उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार स्वामित्व योजना के तहत जिले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशन में स्वामित्व पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में राजस्व विभाग के मैदानी स्तर पर पदस्थ कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। योजना के अंतर्गत निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अभिलेखों का संधारण, आवश्यक जानकारी का संकलन और पंजीयन संबंधी प्रक्रियाओं का संपादन किया जा रहा है।

ग्वालियर व्यापार मेला के लिए 2,090 दुकानें आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध

अब तक 644 आवेदन प्राप्त

ग्वालियर (निप्र)। ग्वालियर व्यापार मेला का आयोजन 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक किया जा रहा है। मेला प्राधिकरण द्वारा 2,090 दुकानों को आरक्षित श्रेणी में शामिल कर आवंटन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इन दुकानों के लिए अब तक कुल 644 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। दुकान आवंटन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि आरक्षित श्रेणी में ऑटोमोबाइल्स, झूला, इलेक्ट्रॉनिक्स, पक्की दुकानें, कोठरी, चबूतरा, सी की दुकानें, रेलवे ट्रैक की दुकानें, डीएनएसटी, एसटी, एक्सपो और एएम की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों का आवंटन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त 644 आवेदनों के माध्यम से मेला प्राधिकरण को लगभग 80 लाख रुपये किराये के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनएसी) के लिए ऑनलाइन माध्यम से 9.35 लाख रुपये की राशि भी प्राधिकरण को प्राप्त हुई है।

कलेक्टर श्री वर्मा ने जनसुनवाई में सुनीं आमजन की समस्याएं

चार जरूरतमंदों को रेडक्रॉस से 32 हजार की आर्थिक सहायता

शिवपुरी (निप्र)। जिला मुख्यालय पर आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने आज सैकड़ों आवेदकों की समस्याओं और शिकायतों को पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ सुना। कई मामलों में उन्होंने मौके पर ही त्वरित निराकरण किया, वहीं शेष आवेदनों के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए चार जरूरतमंदों को रेडक्रॉस मद से कुल



32 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर चेक प्रदान किए। इसमें ग्राम देरखुर्द बछोरा (पोहरी) निवासी महिला लक्ष्मी सेन को 10 हजार रुपए, ग्राम रेहरगावां बधोरा (करैरा) के दिव्यांग युवक सुमित कुमार वंशकार को इलाज हेतु 10 हजार रुपए तथा कमलागंज शिवपुरी निवासी गंभीर बीमारी से ग्रसित जितेंद्र धानुक को इलाज में मदद के लिए 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की



एसडीएम द्वारा कृषि उपज मंडी श्योपुर का निरीक्षण

अनुपस्थित 9 कर्मचारियों के विरुद्ध वेतन काटने के निर्देश

श्योपुर (निप्र)। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में एसडीएम एवं भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी श्योपुर श्री गगन सिंह मीना द्वारा श्योपुर कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंडी में कर्मचारियों की उपस्थिति, साफ-सफाई, किसानों के लिए छाया एवं नीलामी व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के संबंध में नियमानुसार एक दिवस का वेतन राजसात करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये कर्मचारी श्यामा शर्मा, सीमा कौशल, महेन्द्र सिंह, अमित धूलिया, दुष्यंत वर्मा, सुनील धूलिया, अनिल दौहरे का एक-एक दिन का तथा कीर्ति कस्तहार और रफीक अली का आधे-आधे दिन का वेतन काटने के निर्देश मंडी सेक्रेटरी को दिये गये।

साथ ही मंडी परिसर में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। भारसाधक अधिकारी एवं एसडीएम श्री मीना ने मंडी प्रबंधन को निर्देशित किया कि मंडी में उपज विक्रय के लिए आने वाले किसानों के बैठने एवं विश्राम हेतु पर्याप्त छाया की व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त कृषि उपज की नीलामी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसानों को अपनी उपज के विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने मंडी परिसर में व्यवस्थाओं को नियमित रूप से बनाए रखने तथा किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बेटा मम्मी-मम्मी पुकारता रहा, चौथी मंजिल से कूद गई मां

मुरैना में नीचे खड़े परिजन समझाते रहे; गंभीर हालत में ग्वालियर फिर दिल्ली रेफर

मुरैना, निप्र। मुरैना के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने घर की चौथी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल महिला को मुरैना जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे ग्वालियर और फिर दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली में उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना नैनागढ़ रोड की सोमवार तड़के की है। वीडियो आज सामने आया है। वीडियो में महिला घर की चौथी मंजिल की बालकनी से कूदती दिखाई दे रही है। नीचे खड़े परिवार और मोहल्ले के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं रुकी। वीडियो में एक बच्चा महिला को 'मम्मी-मम्मी'



पुकारता सुनाई दे रहा है।

एक महीने पहले किराए पर आया था परिवार

सीएसपी कवीन्द्र सिंह चौहान के अनुसार मुरैना के नैनागढ़ रोड पर रहने वाला एक दंपति मूल रूप से अंबाह का निवासी है। परिवार करीब एक महीने पहले रामहेत सिकरवार के मकान में किराए पर रहने आया था। घर का सामान भी अभी ठीक से व्यवस्थित नहीं हुआ था। परिवार ने यहां दूध डेयरी की दुकान भी खोली थी।

30 मिनट तक महिला को समझाते रहे परिजन

सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे महिला मकान की छत पर पहुंच गईं। डेयरी का काम होने के कारण पति और

आसपास के कुछ लोग पहले से जाग रहे थे। उस समय मॉनिंग वॉक करने वाले लोग भी निकल रहे थे। महिला को छत पर देखकर पति और बच्चे ने उसे नीचे उतरने के लिए समझाया। शोर सुनकर आसपास की महिलाएं भी अपनी छतों पर आ गईं। सभी ने करीब 30 मिनट तक महिला को समझाने और शांत करने की कोशिश की।

महिला नहीं मानी और अचानक छत से कूदी

करीब 30 मिनट तक समझाने के बावजूद महिला नहीं मानी और अचानक छत से छलांग लगा दी। ऊंचाई से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। उसे पहले मुरैना जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस पता लगा रही है कि महिला ने किन परिस्थितियों में जान देने की कोशिश की।

किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है एमपी सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बोले-प्रकृति एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कार्य जारी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण और प्रकृति एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत किसानों की फसलों को जंगली जानवरों, विशेषकर कृष्णमृग एवं नीलगाय से होने वाले नुकसान से बचाने के साथ वन्यजीवों की सुरक्षा

- हेलीकॉप्टर से रंथभंवर में कृष्णमृग-नीलगाय रेस्क्यू अभियान का किया अवलोकन
- दक्षिण एशिया में अपनी तरह का यह पहला प्रयास शाजापुर जिले में हो रहा है साकार

सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शाजापुर जिले में किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष बोमा पद्धति से कृष्णमृग और नीलगाय के रेस्क्यू का अभियान प्रारंभ किया गया था। इस अभियान में दक्षिण अफ्रीका की विशेष टीम की सहायता से वन्यजीवों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर निर्धारित सुरक्षित वन क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रेस्क्यू के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि वन्यजीवों को किसी प्रकार की चोट न पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज शाजापुर जिले के ग्राम रंथभंवर पहुंचकर कृष्णमृगों को सुरक्षित



स्थानों पर पहुंचाने के लिए संचालित प्रोजेक्ट एन्टीलोप ट्रांसलोकेशन अन्तर्गत किए जा रहे रेस्क्यू अभियान के द्वितीय चरण का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियान शाजापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 9 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया जा रहा है। इसके तहत द्वितीय चरण में 2000 कृष्णमृगों के स्थानांतरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि अब तक शाजापुर जिले से लगभग

1236 से अधिक कृष्णमृगों और नीलगायों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू किए गए कृष्णमृगों को श्योपुर के जंगलों, गांधी सागर और रानी दुर्गावती रिजर्व फॉरेस्ट सहित निर्धारित वन क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए 11 ट्रकों की व्यवस्था की गई है। वन्यजीवों के सुरक्षित परिवहन के लिए पशु चिकित्सकों, आवश्यक उपकरणों तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

समस्याओं के हल के लिए सदन पहुंचें मुस्लिम

- शाही इमाम बोले-सियासत में भागीदारी से ही सभी मसले हल होंगे
- रहमानी बोले-सड़क पर प्रदर्शन से एफआईआर होगी, समाधान नहीं

भोपाल। पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि मुस्लिम समाज को अपने धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के स्थायी समाधान के लिए राजनीतिक भागीदारी बढ़ानी होगी। मस्जिदों से जुड़े कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) और दूसरे मुद्दों पर प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने के लिए समाज के लोगों का विधानसभा और संसद तक पहुंचना जरूरी है। सड़क पर प्रदर्शन करने से एफआईआर हो सकती है, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए कानून बनाने वाली संस्थाओं में भागीदारी अहम है। मौलाना बुधवार को भोपाल में कस्तूरबा शिक्षा समिति के एएम हायर सेकेंडरी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान दैनिक भास्कर से खास बातचीत में उन्होंने मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी, वक्फ बोर्ड की नई बॉडी में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति, सामाजिक एकता और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की राजनीतिक रणनीति पर अपनी बात रखी।



फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल हों

भोपाल में वक्फ बोर्ड की नई बॉडी में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने के सवाल पर मौलाना ने कहा कि मुस्लिम समाज की परेशानी की एक बड़ी वजह राजनीतिक भागीदारी की कमी है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रतिनिधि कानून बनाने वाली संस्थाओं में पहुंचेंगे, तो संबंधित कानूनों और व्यवस्थाओं पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकेंगे। मस्जिदों में अज्ञान से जुड़े नियमों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केवल मुतवल्ली की भूमिका नहीं होती, बल्कि संबंधित संस्थाओं और कानून बनाने वाली व्यवस्था के फैसले भी महत्वपूर्ण होते हैं।

पैगंबर साहब ने दूसरे समुदायों से किया था संवाद

मौलाना ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना हिजرات करने के बाद के प्रसंग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वहां अमन और सुरक्षा के इंतजामों के लिए दूसरे समुदायों के साथ संवाद और समझौते किए गए। उनके मुताबिक, यह उदाहरण बताता है कि समाज के हितों और सुरक्षा के लिए राजनीतिक समझदारी तथा दूसरे समुदायों के साथ सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस देश में हम रहते हैं, वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी के जरिए ही अपने अधिकारों और हितों को प्रभावी ढंग से सामने रखा जा सकता है। समाज को राजनीति से दूरी बनाने के बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपनी मौजूदगी मजबूत करनी चाहिए।

एक्टिवा-जूपिटर से शराब की सप्लाई, घेराबंदी कर दबोचा

भोपाल में होटल,रेस्टोरेंट-ढाबों पर कार्रवाई, 10 से ज्यादा केस दर्ज

भोपाल। भोपाल में एक्टिवा और जूपिटर से शराब की सप्लाई करने पर आबकारी विभाग ने दो लोगों को पकड़ा है। इनके पास से अवैध शराब जब्त की गई। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी सर्चिंग की गई। इस दौरान अवैध शराब पिलाने के 10 से ज्यादा केस बनाए गए। यह कार्रवाई मंगलवार-बुधवार की रात हुई। आबकारी कंट्रोलर वर्षा डूके ने बताया कि सहायक जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैन व टीम ने घोड़ा नक्शा निवासी चंचल साहू को एक्टिवा से अवैध रूप से शराब परिवहन करते हुए पकड़ा। इसके बाद उसके घर की तलाशी लेने पर 15 बोतल विदेशी शराब भी मिली। इसी तरह सहायक जिला आबकारी अधिकारी शरद मिश्रा व टीम ने पीएंडटी चौराहा के पास से जूपिटर से अवैध शराब की सप्लाई करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके विरुद्ध मद्रा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रीति डूके ने बैरगाढ़ क्षेत्र के एवं उप निरीक्षक स्वाति बघेल ने करोड़ क्षेत्र में संचालित होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट पर सर्चिंग की। यहां संचालक और शराब के अवैध सेवन पर 10 से अधिक केस बनाए गए।

साइकिल और ई-वाइक चलाने के लिए निकलेगा टैंडर

आईएसबीटी परिसर में रखी साइकिलों और इलेक्ट्रिक साइकिलों का संचालन शुरू कराने की तैयारी भी की जा रही है। निगम इन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर चलाने के लिए निविदाएं जारी करेगा। निगम आयुक्त ने कहा कि वे स्वयं इन साइकिलों और ई-बाइक का परीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने वर्मा ट्रेवल्स के मैनेजर से चर्चा की और गैर संचालित बसों को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईएसबीटी से बसों का संचालन करने वाली अन्य ट्रेवल्स एजेंसियों के संचालकों के साथ भी बैठक की जाएगी।

ओमप्रकाश बनेंगे आनंद संस्थान के सीईओ

मोहन सरकार ने सौंपा जिम्मा,सीएम

ऑफिस में बने रहेंगे राजेश हिंगणकर

भोपाल। नर्मदा परिक्रमा कर चुके रिटायर्ड आईएसएस अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव को मोहन सरकार ने राज्य आनंद संस्थान का सीईओ बनाया है। वहीं, रिटायर्ड आईपीएस



अधिकारी राजेश कुमार हिंगणकर को एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें एक साल के लिए सविदा सेवा वृद्धि दी गई है। मोहन कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में आनंद विभाग की ओर से ओमप्रकाश श्रीवास्तव को राज्य आनंद संस्थान के सीईओ पद पर सविदा नियुक्ति देने का प्रस्ताव लाया गया था। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग इसके आदेश जारी करेगा। ओमप्रकाश श्रीवास्तव शिवपुरी, रीवा समेत कई

जिलों में कलेक्टर रहे हैं। उन्होंने गृह विभाग के सचिव, आबकारी आयुक्त और जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी भी निभाई है। श्रीवास्तव ने पिछले साल अपनी पत्नी के साथ नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अलावा वे साहित्यिक पुस्तकें भी लिख चुके हैं। राज्य सरकार ने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार हिंगणकर को एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) के पद पर सविदा नियुक्ति दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, हिंगणकर 1 नवंबर 2026 से एक साल तक ओएसडी के रूप में काम करते रहेंगे। हिंगणकर की ओएसडी पद पर सविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें 4 दिसंबर 2024 को जारी आदेश के अनुसार प्रभावी रहेंगी।

राजधानी में दिवाली पर रहेगी जबरदस्त सख्ती

पटाखा दुकानों के पास तैनात रहेंगी फायर टीमें



भोपाल। दिवाली पर पटाखों की खरीदारी और आतिशबाजी के दौरान आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। पटाखा बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अग्निशमन वाहन व प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात रहेंगे। बिजली के तारों और ट्रांसफॉर्मर के आसपास पटाखा दुकान लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग और ऊर्जा विभाग ने त्योहार के दौरान आग और बिजली से जुड़े हादसों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को पटाखा बिक्री स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। बाजारों में बिजली के खुले तारों और ओवरलोडिंग की जांच भी होगी। प्रशासनिक टीमें दुकानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पटाखा

कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिजली की लाइन या ट्रांसफॉर्मर के नीचे और उनसे सटाकर दुकानें नहीं लगाई जाएं। दुकानों में रोशनी के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। स्वीकृत क्षमता से अधिक बिजली इस्तेमाल करने और सीधे तार डालकर बिजली लेने पर कार्रवाई हो सकती है। आतिशबाजी के दौरान भी बिजली के खंभों, तारों और ट्रांसफॉर्मर से दूरी बनाए रखना जरूरी है। पटाखों की चिंगारी से बिजली के उपकरणों में आग लगने या अन्य हादसे का खतरा रहता है।

बाजारों में पांच व्यवस्थाओं पर रहेगा जोर- पटाखा बिक्री स्थलों पर अग्निशामक यंत्र, पानी और रेत की व्यवस्था रखनी होगी। दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी और आने-जाने के रास्ते खुले रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में दमकल वाहन और बचाव दल आसानी से पहुंच सकें। बिजली कनेक्शन की जांच के साथ स्वीकृत लोड से अधिक खपत पर भी नजर रखी जाएगी।

हलालपुरा की आग ने बढ़ाई थी चिंता

भोपाल के हलालपुरा क्षेत्र में पटाखा दुकान और गोदाम में आग लगने के दौरान लगातार धमाके हुए थे। आग की लपटें करीब 70 फीट तक उठी थीं। आग बुझाने के लिए आसपास की बिजली आपूर्ति भी बंद करनी पड़ी थी। इसके अलावा अप्रैल 2017 में इंदौर के रानीपुरा में पटाखा दुकान में आग से पांच लोगों की मौत हुई थी। जून 2017 में बालाघाट की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 25 लोगों की जान गई थी। अक्टूबर 2022 में मुरैना के बानमोरे में पटाखे रखने और बनाने के दौरान हुए विस्फोट में चार लोगों की मौत हुई और छह घायल हुए थे। इन हादसों को देखते हुए त्योहार के दौरान पटाखा बाजारों में सुरक्षा नियमों का पालन और समय रहते जांच को अहम माना जा रहा है।

भोपाल में आगजनी के बाद जागा प्रशासन

आईएसबीटी में लगेंगे फायर हाइड्रेंट, महीनों से खड़ी बसें हटेंगी, और कई बदलाव

भोपाल। आगजनी की घटनाओं के बाद अब प्रशासन ने बस टर्मिनस की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद शुरू की है। कुशाभाऊ ठककर अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (आईएसबीटी) में आग से बचाव के लिए फायर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे और बिजली की वायरिंग की जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही परिसर में लंबे समय से खड़ी गैर संचालित बसों को हटाने और उनके संचालकों से किराया वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने आईएसबीटी का निरीक्षण कर सुरक्षा, सफाई और बसों के संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार करने को कहा। आईएसबीटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फायर हाइड्रेंट स्थापित करने के निर्देश दिए



हैं। इसके साथ ही परिसर में बिजली की वायरिंग की जांच कराई जाएगी, ताकि संभावित खतरों की पहचान कर जरूरी

सुधार किए जा सकें। परिसर की नियमित सफा-सफाई और व्यापक स्तर पर धुलाई कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।